बिजनेस स्टैंडर्ड, भोपाल
04 JUN 2011

गेहूं की सरकारी खरीद में मध्य प्रदेश अव्वल

शशिकांत त्रिवेदी
भोपाल, 3 जून

मध्यप्रदेश में इस साल राज्य सरकार ने गेहूं की 50 लाख टन गेहूं का रिकार्ड सरकारी खरीद कर किसानों को प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले रबी के मौसम में होनेवाली सरकारी खरीद की योजना बनानी शुरू कर दी है। इसके लिए गेहूं उत्पादकों को एक निश्चित मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजना होगा कि वे कितना गेहूं सरकारी एजेंसियों को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी गेहूं उत्पादकों के लिए ई भुगतान प्रणाली लागू करने की भी योजना है। यद्यपि इसके अलावा सभी किसानों के जमीन रिकार्ड की भी जांच की तैयारी चल रही है। मध्यप्रदेश की सरकार ने इस साल गेहूं खरीद पर कुल 5300 करोड़ रुपये व्यय किये, जिसमें किसानों को दिया गया 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी शामिल था। इससे मध्यप्रदेश गेहूं की सरकारी खरीद में अव्वल रहने वाले देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हो गया।

सूबे के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की सरकारी खरीद अपने बूते की है, जबकि बाकी राज्यों में अभी भी आढ़तिया प्रणाली है। उन्होंने बताया कि हम जमीन के रिकार्ड का सत्यापन करने की योजना बना रहे हैं। अगले साल से ई भुगतान योजना लागू की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण योजना यह है कि किसानों को अगले मार्च से शुरू होनेवाले रबी मौसम में होनेवाले सरकारी खरीद के लिए, वे जितना गेहूं बेचना चाहते हैं उन्हें सरकारी एजेंसियों को एसएमएस के माध्यम से गेहूं की मात्रा बतानी होगी। यह योजना प्रदेश को दो जिलों हरदा और भिंड में लागू की गई थी। फिलहाल किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद राज्य वितरण संघ और नागरिक आपूर्ति निगम कर रहा है। जबकि आईटीसी, कारगिल और हिंद जैसी निजी खरीद एजेंसियों का हमारे पास कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है।

प्रदेश के कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि निजी मंडियों में खरीद का आंकड़ा घट कर एक लाख टन तक सिमट गया है। पिछले कुछ सालों पहले यह आंकड़ा 5 लाख टन तक हुआ करता था। इसका कारण है कि सरकार की तरफ से किसानों को गेहूं का अधिक मूल्य दिया जाता है। गांव भाउखेड़ी के गुलाब सिंह जैसे किसानों को आईटीसी द्वारा चलाए जा रहे ई चौपाल में सुजाता और शरबती गेहूं का ज्यादा भाव नहीं मिला। उनका कहना है कि केवल सरकारी एजेंसियां ही अच्छे दाम देती है। दूसरी तरफ बाजार के

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद निजी कंपनियों ने गेहूं खरीद से अपना हाथ पीछे खींच लिया। निजी क्षेत्र वाले सस्ती दर पर गेहूं प्राप्त करने के लिए नजदीक के राज्यों जैसे की उत्तर प्रदेश जाकर खरीदारी कर रहे हैं, जहां गेहूं का मूल्य मध्य प्रदेश के 1150-1200 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 950 रुपये प्रति क्विंटल ही है। पिछले साल निजी क्षेत्र ने मध्य प्रदेश से 5 से 7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की थी। मध्य प्रदेश में 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की कई किस्मों की खेती होती है।